Toppersnotes

Unleash the topper in you

MP - PSC

State Civil Services

Madhya Pradesh Public Service Commission

पेपर - 3 भाग - 1

अर्थव्यवस्था

(भारत एवं मध्यप्रदेश)

SIERRA INNOVATIONS

विषय-सूची

1. मुद्रास्फीति	1
2. उदारीकरण	7
3. IT की नीति	8
4. राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद	9
5. लोक वित्त	26
6. भारत सरकार के खर्चे	34
7. वित्त आयोग	38
8. मूल्य संवर्द्धन कर	40
9. वस्तु एवं सेवा कर	42
10. कर टालना	45
11. भारतीय रिजर्व बैंक	47
12. गैर निष्पादित संपत्ति	56
13. वित्तीय समावेश	62
14. वित्त बाजार	65
15. भारत के मुद्रा बाजार	66
16. भारत के इक्विटी व्यापार	68
17. मुद्रास्फीति और भविष्य के बाजार	76
18. स्टार्टअप	78
19. भारत के विदेशिक क्षेत्र	81
20. मुद्रा की परिवर्तनीयता	85
21. विदेशी व्यापार नीति	86
22. विनिमय दर	91
23. क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी	95
24. टोटलाइजेशन (समझौता)	96

25. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन 97

26. समावेशी विकास 107

27. कृषि सब्सिडियों का विकास 111

28. न्यूनतम समर्थन मूल्य 117

29. सार्वजनिक वितरण प्रणाली 126

30. कृषि विपणन प्रणाली 131

31. पशुपालन का अर्थशास्त्र 140

32. भूमि सुधार 143

33. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 152

34. सरकारी बजट 159

35. कालाधन/ कर चोरी 163

36. धन-शोधन 168

37. आधारभूत संरचना 173

38. निवेश मॉडल 180

39. बौद्धिक संपदा अधिकार 183

40. आर्थिक उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 187

41. औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक नीति पर नीति पर इसका प्रभाव 194

42. गरीबी 197

43. बेरोजगारी 203

44. खाद्य सुरक्षा 206

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था

1.जनांकीय परिदृश्य	212
2.शिक्षा	218
3.ऊर्जा	220
4.उद्योग	225
5.कृषि आधारित उद्योग	231
6.खनिज आधारित उद्योग	235
7.परिवहन	239
8.संचार एवं समाचार पत्र	243
9.ऊर्जा संसाधन	247
10.ऊर्जा प्रबंधन-मुद्दे एवं चुनौतियाँ	254
11.ऊर्जा प्रबंधन के कदम	260
12.ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य	261

Toppersnotes
Unleash the topper in you

Inflation (मुद्रा स्फीति)

प्रस्तावनाः-

मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है जिसमें चयनित वस्तुओं की कीमत स्तर (Price Level) बढने लगता है।

मुद्रा स्फीति एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा होती है क्योंकि इससे न केवल देश का जीडीपी व रोजगार प्रभावित होते हैं बल्कि इससे सामाजिक न्याय की संकल्पना पर भी प्रभाव पडता है।

मुद्रास्फीति का मापनः-

मुद्रास्फीति को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि WPI(wholesale price index) थोक मूल्य सूचकांक, CPI(consumer price index) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, PPI(producer price index) उत्पादक मूल्य सूचकांक

कीमत सूचकांकों का प्रयोग करने से मुद्रास्फीति की गणना करना आसान हो जाता है। कीमतों से कीमत सूचकांक की ओर जाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है-

P_1/P_0 X100

P_1= चालू मूल्य या प्रचलित मूल्य (current price)

P_0= आधार मूल्य (base price)

भारत में मुद्रास्फीति की गणनाः-

भारत सरकार द्वारा MPI को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इस संदर्भ में office of economic advisor (Ministry of Commerce and industry) द्वारा प्रत्येक माह में मुद्रास्फीति के आंकडे जारी किए जाते हैं।

KBI द्वारा मुद्रास्फीति के संदर्भ में कोई भी निर्णय करने तथा IT (Inflation Targeting) की नीति को संचालित करने के लिए CPI-Ns (new series) का प्रयोग किया जाता है ।CPI-Ns को CSO(Central Statistics Office) द्वारा तैयार किया जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि WPI की तुलना में CPI को मुद्रास्फीति का बेहतर मानदंड माना जाता है इसके पीछे दो मुख्य कारण-

1. WPI में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है जबकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में सेवाओं की भूमिका होती। उपर्युक्त के विपरीत, CPI में सेवाओं का समाविष्ट होता है।
2. WPI थोक स्तर की कीमतों को ध्यान में रखता है जबकि CPI उपभोक्ता स्तर की कीमतों पर ध्यान रखता है ।

   WPI कि उपर्युक्त कमियों के मद्देनजर CPI के प्रयोग को वरीयता दी जा रही है, यही कारण है कि IT की Policy की CPI–Ns को ध्यान में रखा गया ।

   भारत में मुद्रास्फीति की दर निकालने के लिए Point to Point अथवा Year on Year विधि का प्रयोग किया जाता है ।

इस विधि के अंतर्गत यदि दिसंबर 2016 के लिए मुद्रास्फीति की दर की गणना करनी है तो दिसंबर 2015 के WPI/CPI के मूल्य के साथ की जाएगी और प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाएगा। यह प्रतिशत परिवर्तन ही दिसंबर 2016 के लिए मुद्रास्फीति की दर होगी।

उदाहरणः–

CPI-Ns-2012

टमाटर–20

2016	2015
Jan	Jan
Feb	Feb
.	.
.	.
.	.
Dec 440	Dec 400

उपर्युक्त चित्र को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दिसंबर 2016 की मुद्रास्फीति की दर $\frac{40}{400} X100$ होगी।

$$\frac{40}{400} \times 100 = 10\%$$

Dec. 2016	Dec. 2015	
440	400	→ $\frac{40}{400} \times 100 = 10\%$
132.8	127.9	→ $\frac{4.9}{1000} \times 100 = 3.8\%$

कभी–कभी मुद्रास्फीति की दर गणितीय रूप से अत्यधिक ऊंची अथवा कम दिखाई देती है, इसे Base effect का जाता है।

Base effect उन वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनकी कीमतें Fluctuate करती हैं । भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित दो प्रकार की वस्तुएं Base effect उत्पन्न करती हैं –

1. food articles (खाद्य वस्तुएं)
2. ईंधन से जुडी वस्तुएं जैसे कि cruide oils

भारत में मानसून आदि कारणों से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढाव उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार Opec आदि समूह कच्चे तेल की आपूर्ति में परिवर्तन करके इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं । जैसा कि हाल ही में देखा गया ।

इसके अलावा भारतीय रुपए की विनिमय दर में होने वाले बदलाव भी कच्चे तेल की घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालते हैं ।

<u>Production:-</u>

<u>2001-02</u> ↓ 100

<u>2002-03</u> -7.2% ↓ 93

<u>2003-04</u> 10% ↓ 100

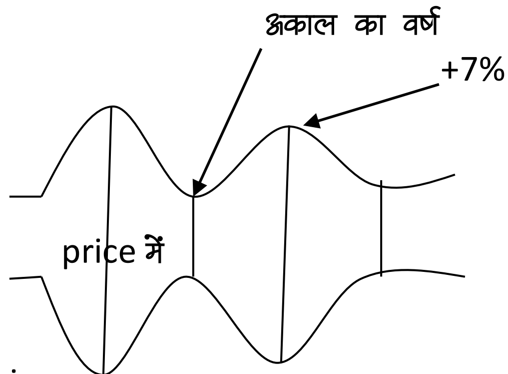

price

Base effect
2012=100
Tomato=20

Dec,16

Rs 80 $=\frac{80}{20}X100$= 400

Dec,15

RS 80 $=\frac{80}{20}X100$ =400

0% inflation

Core inflation v/s Head lines inflation:-

आधार प्रभाव की समस्या के निराकरण के लिए मुद्रास्फीति की गणना से खाद्य तथा ईंधन से जुडी वस्तुओं को हटा दिया जाता है इन्हें हटाने के बाद प्राप्त की गई मुद्रास्फीति की दर को core inflation कहते हैं। उपर्युक्त के विपरीत Head line inflation के मामले में इन वस्तुओं को नहीं हटाया जाता है।

RBI किसी भी मौद्रिक निर्णय हेतु core inflation पर विशेष रूप से ध्यान देता है जबकि सामान्य जनता के लिए Head line inflation के आंकडे जारी किए जाते हैं ।

Demand pull inflation v/s Cost-Push inflation:-

जब मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण समग्र मांग (Aggregate demand) अधिकता हो तो ऐसी मुद्रास्फीति को Demand-pull inflation कहते हैं। समग्र मांग के अंतर्गत ब्याज दरों का कम होना, तरलता अथवा मुद्रा का प्रसार, सरकारी खर्च का अधिक होना, निर्यातों का बढना, उपभोग का बढना आदि कारकों को शामिल किया जा सकता है।

Cost-Push inflation में वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने का कारण समग्र मांग में अधिकता नहीं होती है इसका मुख्य कारण उत्पादन की लागतों का ऊंचा होना होता है इसके अलावा भारत जैसे राष्ट्रों में निम्न स्थितियां देखने को मिलती है–

1. supply bottlenecks वस्तुओं की आपूर्ति में विभिन्न प्रकार की बाधाएं
2. Supply inelasticity- बढ़ी हुई कीमत पर आपूर्ति अधिक नहीं बढ़ पाती है
   उदाहरणः– नमक

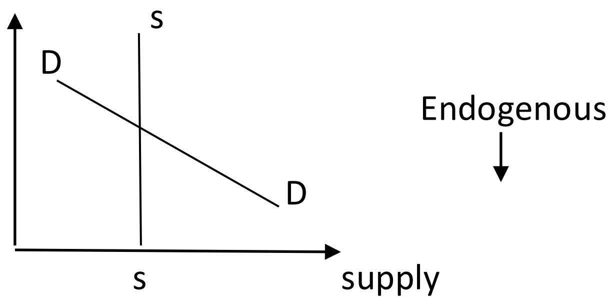

3.Exogenous supply shocks:-

बाह्मय आपूर्ति के झटके जैसे मानसून का कम रह जाना, oil shocks (1970) etc

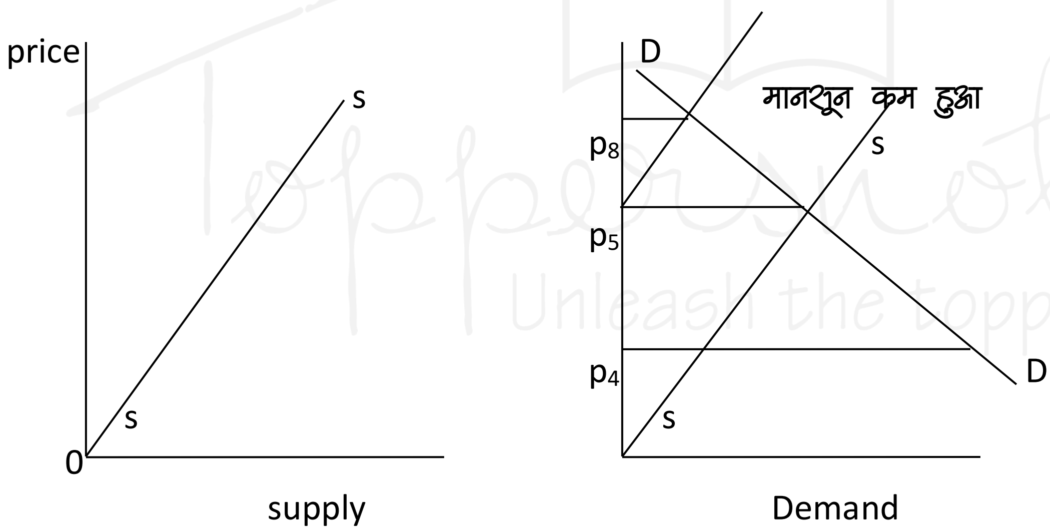

इस प्रकार भारत की मुद्रा स्फीति cost-push प्रकार की है लेकिन यह देखा गया है या देखा जाता है कि भारत में अधिकांश मामलों में Demand Management policies को लागू किया जाता है जिसमें ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तथा तरलता को नियंत्रित किया जाता है इससे तत्कालिक रूप से लाभ तो होता है लेकिन स्थाई समाधान नहीं मिल पाता है।

4. **Growth,Unemployment and inflations:-**

यह ध्यान देने योग्य है कि GDP की growth rate तथा मुद्रास्फीति के मध्य सकारात्मक संबंध पाया गया है इसका निहितार्थ यह हुआ कि यदि GDP की growth rate बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी।
इसी प्रकार बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध पाया गया है इसका निहितार्थ यह हुआ कि यदि बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी।

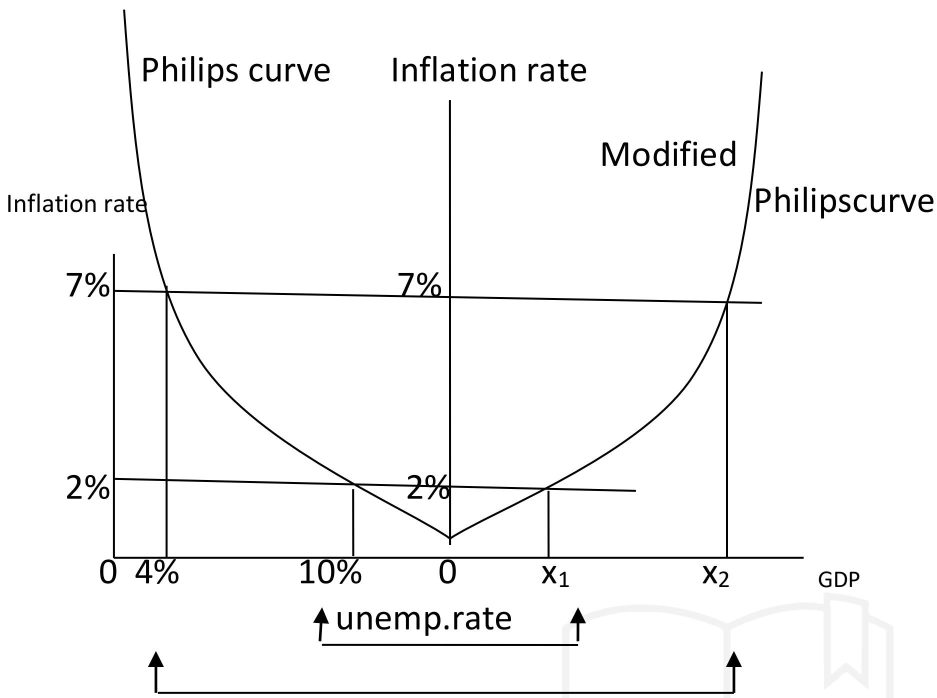

उपर्युक्त चित्र के अनुसार शुरुआत में बेरोजगारी की दर 10 प्रतिशत है यदि बेरोजगारी की दर को कम करना है तो जीडीपी को बढावा देना होगा इस संदर्भ में ब्याज दरों को कम किया जाएगा, तरलता का विस्तार, टैक्स में छूट दे दी जाएगी तथा उत्पादकों को निवेश सब्सिडी दिए जाएंगे

इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन को बढावा मिलेगा, इससे श्रमिकों की मांग बढेगी जिससे मजदूरियां बढने लगेंगी जिसके फलस्वरूप wage inflation आने लगेगा यदि wage inflation के साथ श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढती तो वस्तुएं महंगी हो जाएगी जिससे inflation का स्तर High हो जाएगा।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) :-

- यह सूचकांक थोक मूल्यों पर आधारित है ।
- 2014 तक भारत में इसे मुद्रास्फीति के मापन में प्रयोग में लाया जाता था ।
- यह सूचकांक उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ।
- WPI केवल वस्तुओं पर आधारित होता है ।
- निम्न प्रकार के WPI घोषित किये जाते हैं ।

(1) प्राथमिक वस्तुओं का WPI :- इसमें खाद्य पद्धार्थों को शामिल किया जाता है । इसमें 117 वस्तुएँ शामिल हैं ।

(2) ईंधन का WPI :- इसमें 16 वस्तुएँ शामिल की जाती हैं ।

(3) विनिर्मित वस्तुओं का WPI :- इसमें 564 विनिर्मित वस्तुएँ शामिल की जाती हैं ।

(4) मुख्य WPI :- उपरोक्त सभी को सम्मिलित करते हुए मुख्य WPI ज्ञात किया जाता है।

- इसमें 697 वस्तुएं शामिल की जाती है।
- WPI की घोषणा प्रत्येक महीने की 14 तारीख को की जाती है।
- WPI का वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(CPI)** :-

- यह उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित सूचकांक है।
- 2014 ई. में इसे भारत का मुख्य सूचकांक घोषित किया गया।
- वर्तमान में RBI द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए CPI का उपयोग किया जाता है।
- CPI में वस्तुओं के साथ सेवाओं में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है।
- इसकी घोषणा MOSPI, CSO (Central Statistics Office) द्वारा की जाती है।
- इसकी गणना हेतु वस्तु एवं सेवाओं के समूह को आधार बनाया जाता है।
- इसे वस्तु और सेवाओं की Basket कहा जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्र की Basket में 448 व शहरी क्षेत्र की Basket में 960 वस्तु और सेवाएँ शामिल की जाती है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग CPI ज्ञात किया जाता है।
- इनके आधार पर एक सामूहिक CPI घोषित किया जाता है।
- CPI की घोषणा प्रत्येक महीने की 11 तारीख को की जाती है।
- CPI में खाद्य पदार्थों को 60% भारांश दिया जाता है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम आधारित CPI की घोषणा की जाती है। जैसे- औद्योगिक श्रम का CPI
- CPI के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व मनरेगा मजदूरी आदि ज्ञात की जाती है।
- विश्व के लगभग 157 देशों में इसे अपनाया जाता है।
- इसका आधार वर्ष 2012 ई. है।

उदारीकरण

उदारीकरण शब्द की उत्पत्ति राजनीतिक विचारधारा 'उदारवाद' से हुई है, जोकि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई थी (यह वस्तुतः पिछली तीन शताब्दियों में विकसित हुई थी)
उदारीकरण शब्द का अर्थव्यवस्था में वहीं अर्थ होगा, जोकि इसके मूल शब्द उदारवाद का है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक या पूंजीवादी समर्थक की ओर आर्थिक नीतियों का झुकाव ही उदारीकरण है। हमने 1970 के दशक में इसे सम्पूर्ण यूरो–अमरीका और विशेषकर 1980 के दशक में होते हुए देखा है इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण 1980 दशक मध्य में चीन है, जब इसने 'खुले द्वार की नीति' की घोषणा की थी। यद्यपि चीन में आज भी कुछ विशिष्ट उदारवादी लक्षणों का अभाव है। उदाहरण के लिए व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रणाली इत्यादि हैं। फिर भी चीन को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा गया।

अन्य शब्दों में, उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किये जाये, जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें।

- उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पडे।
- उदारीकरण व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है और सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किये है।
- उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का वह परिणाम है जो 'लाइसेंस प्रणाली' को समाप्त कर देता है।
  तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा व्यापार नीति को उदार बनाना जो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर टैरिफ, सब्सिडी और अन्य प्रतिबंधों को हटा रहा है, उदारीकरण के नाम जाना जाता है।

उदारीकरण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है :-

1. लाइसेंसिंग प्रणाली को न्यूनतम तथा सरल बनाना।
2. सरकारी नियंत्रणों के स्थान पर बाजार शक्तियों को प्रोत्साहित करना।
3. स्कन्ध विपणित क्रियाओं को नियमित करना।
4. वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगी बाधाओं को हटाना।
5. नवीन उद्योगों की स्थापना को स्वतंत्रता देना।
6. इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त करना अथवा न्यूनतम करना।
7. वस्तुओं की कीमत का निर्धारण उत्पादकों/निर्माताओं द्वारा किया जाना।
8. आयात नीति को सरल बनाना।
9. उत्पादों के वितरण पर लगी रोकों को हटाना।

IT की नीति

प्रस्तावना:–

भारत में इस नीति को हाल ही में लागू किया गया है इसे उर्जित पटेल समिति तथा FSLR (Financial sector legislative Reforms commission) की सिफारिशों पर लागू किया गया है ।

उपयुक्त रणनीति के अंतर्गत भारत में CPI-Ns based inflation को 4%(±2.1) के दायरे में रखने की कोशिश की जाएगी ताकि देश मे Price stability को बनाए रखा जा सके और आवश्यक Expectations को नियंत्रित किया जा सके। यह ध्यान देने योग्य है कि Price stability से दीर्घकाल में growth को बढावा मिलता है क्योंकि लोग आसानी से निर्णय कर सकते हैं।

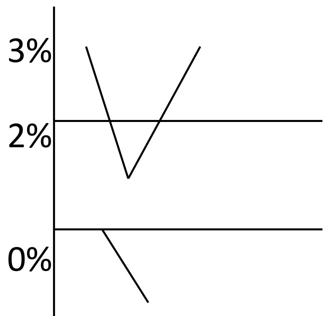

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की IT flexible है ना कि inflexible ।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:–

भारत में IT की रणनीति का लागू होना एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम है इससे देश में दीर्घकाल में growth को बढावा मिलेगा। इस नीति के लागू होने से मौद्रिक नीति का निर्माण अधिक अनुशासन में आएगा। मौद्रिक नीति में पारदर्शिता एवं जवाबदेही उत्पन्न होगी।

उपर्युक्त के बावजूद इस नीति के संचालन में निम्न बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती–

1. भारत की मुद्रा स्फीति मुख्यतः cost push प्रकार की है ऐसी स्थिति में Repo rate की बदलाव सफलता की सीमित रखते हैं।

2. IMF के अनुसार भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में बडी मात्रा में मौद्रिक लेनदेन होते हैं ऐसी स्थिति में रेपो रेट में बदलाव करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना कठिन होगा।

3. IMF के अनुसार भारत के Banks Repo rate में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ग्राहकों से वसूली की जाने वाली ब्याज दर में परिवर्तन नहीं करते।

4. भारत में RBI पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है तथा MPCE के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
   अगले 5 वर्ष हेतु IT का लक्ष्य भी सरकार द्वारा तय किया गया है अतः IT की रणनीति पूर्ण रूप से राजनीति से मुक्त नहीं हो सकी है।

राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद
National income & Product

प्रस्तावना:-

अर्थव्यस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है । अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुडी अवधारणों का स्पष्ट होना आवश्यक है । वैसे तो इसका पता सामान्य तौर पर देश और वहां के लोगो की खुशहाली और उनकी प्रसन्नता से लगाते है । यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है हालांकि हम यह जान चुके है कि आय से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इस राय के पीछे कई वजहें भी है । जब 1990 के शुरूआत सालों में मानव विकास सूकांक की शुरूआत हुई । इस सूचकांक में किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई थी । लेकिन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रो में भी पैमाने पर निवेश किया जाता हो । यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है ।

अन्य शब्दो में -

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है अर्थात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) :- एक वित्त में किसी देश के निवासियों द्वारा देश की आर्थिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है ।

अंतिम वस्तु एवं सेवा-

- उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तुएं दो प्रकार की होती है ।
  (1) मध्यस्थ वस्तुएं- ऐसी वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती है, मध्यस्थ वस्तुएं कहलाती है। अर्थात यह वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग में नहीं ली जाती । जैसे- कार का इंजन

  (2) अंतिम वस्तुएं - ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है अर्थात इनमें उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है और उत्पादन संभव नहीं होता है । जैसे- कार
- दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यस्थ वस्तुओं को छोड दिया जाता है और केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है ।
- भारत की GDP गणना अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे GVA (सकल मूल्य संवर्द्धन) आधारित बनाया गया ।

  (1) GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit

  (2) $GVA_{bp} = GVA_{fc} +$ उत्पादन कर - उत्पादन Subsidy

  (3) $GDP_{mp} = GVA_{bp} +$ उत्पाद कर - उत्पाद Subsidy

- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते है, आधार मूल्य कहलाता है ।

वित्त वर्ष :-

- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूंढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया
  (1) बेल्बी आयोग
  (2) L. K. JHA समिति
  (3) दार्निश वाचा समिति
  (4) शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)

उत्पादन कर- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगने वाला कर । जैसे- कच्चे माल पर लगने वाला कर

उत्पादन Subsidy- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली Subsidy । जैसे- स्वदेशी कच्चे माल पर Subsidy

उत्पाद कर- अंतिम उत्पाद कर प्रति इकाई पर लगाया जाने वाला कर । जैसे- Excise Duty, GST etc. यह कर अंतिम उपभोक्ता से वसूला जाता है जबकि उत्पादन कर उत्पादक से लिया जाता है ।

उत्पाद Subsidy- अंतिम उत्पाद पर उपभोक्ता को दी जाने वाली Subsidy जैसे- Subsidy on Bettey Car

जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न है :-

1. GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (Growth Rate) है उदाहरण के लिए किसी देश की GDP 107 रूपया है और यह बीते साल से 7 रूपया ज्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है । जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकॉनमी कहते है तो मतलब यह होता है कि देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ रही है ।
2. यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है । इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है । लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नही चल पाता है ।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है ।

एनडीपी (NDP):-

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) :-

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से मूल्य ह्रास घटाकर इसकी गणना की जाती है।
- विभिन्न देशों में मूल्य ह्रास की गणना अलग-अलग विधियों से की जाती है । इसलिए NDP का आधार प्रत्येक देश में समान नहीं होता ।
- इस कारण NDP का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।

अन्य शब्दो में :-

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP), किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है । वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है जिसका मतलब उस सामान का घिसने (Depreciation) या टूटने-फूटने से होता है । इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है । भारत में यह फैसला केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है । यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादो में होने वाली मूल्य कटौती (घिसावट)की दूरी तय होती है ।

इस तरह से देखें तो NDP=GDP-घिसावट

ऐसे जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगी । अवमूल्यन की शून्य करने का कोई भी तरीका नही है । लेकिन मानव समाज इस अवमूल्यन को कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है ।

मूल्य ह्रास :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है ।

NDP का अलग-अलग प्रयोग निम्न है :-

(a) घरेलू इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है । इतना ही नही खास समयावधि के दौरान उद्योग धंधे और कारोबार में अलग-अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है ।
(b) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ।

लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नही किया जाता है । ऐसा क्यों है? इसकी वजह है कि दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग-अलग दरें निर्धारित करती है । यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती है ।

जीएनपी (GNP) :-

किसी अर्थव्यवस्था में ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट (GNP) उस आय को कहते है जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोडकर हासिल होता है । इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है । या,

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) :- एक वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GNP कहलाता है ।

(1) $GNP_{mp} = GDP_{mp}$ + Net factor Income from abroad (NFIFA)
(2) NFIFA = Income of Indian Citizen outside India – Income earned by foreigner in India

विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल हैं :-

Toppersnotes
Unleash the topper in you

1. निजी प्रेषण (Private Remittances)
2. विदेश कर्जे पर ब्याज (Interest of the External Loans)
3. विदेश अनुदान (External Grants)

सामान्यतः फार्मूले के मुताबिक GNP, GDP+ विदेशों से होने वाली आय के बराबर है। लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है लिहाजा भारत का GNP हमेशा GDP विदेशों से होने वाली आमंदनी के बराबर होता है। यानी भारत का GNP हमेशा GDP विदेशों से होने वाली आमंदनी के बराबर होता है। यानी भारत का GNP हमेशा GDP से कमतर होता है।

GNP के विभिन्न उपयोग इस तरह से है –

i. इससे राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) दुनिया के देशो की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता (PPP) के आधार पर रैंक करता है।
ii. राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से GNP, GDP की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीरें भी पेश करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की आतंरिक के साथ-साथ बाहरी ताकत को भी बताता है।
iii. यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफी मदद करता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है।

एनएनपी (NNP) :-

ग्रॉस नेशलन प्रॉडक्ट (GNP) में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते है।

या

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद **(NNP)** :-

- इसकी गणना के लिए GNP में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है।
- भारत में कारक लागत पर NNP को राष्ट्रीय आय माना जाता है।
- बाजार मूल्य/वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) कहा जाता है।
- $NNP_{mp} = GNP_{mp} -$ Dep.(मूल्य ह्रास)
- $NNP_{fc} = NNP_{mp} -$ अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} / \frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp} -$ मुद्रास्फीति (CP = -स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक GDP भी कहा जाता है।
- बाजार मूल्य पर GDP को Nominal GDP भी कहा जाता है।

GDP Deflator = $\frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} / \frac{\text{GDPmp}}{\text{GDPcp}}$

NNP के विभिन्न उपयोग इस तरह से है :-

i. यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (National Income) (NI) है। यद्यपि GDP, NDP और GNP सभी राष्ट्रीय आय ही है लेकिन नेशनल इनकम (NI) के तौर पर नही लिखा जाता ।

ii. यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ।

iii. जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते है तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है । यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है ।यहां एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है ।ऐसे में किसी देश में मूल्य कटौती की दर ज्यादा होने पर प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है ।

- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है ।
- राष्ट्रीय आय के लिए आकडों का संकलन NSSO & CSO द्वारा किया जाता है ।
- यह दोनों संस्थाएँ MOSPI के अन्तर्गत कार्य करती है ।

(1) MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)

(2) NSSO = National Sample Survey Office/Organization (राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन)

CSO = Central Statistics Office (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन)

- राष्ट्रीय आय की गणना चार मूल्यों पर आधारित होती है ।

(1) कारक लागत

(2) <u>बाजार मूल्य</u>- वह मूल्य जिस पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा वस्तुएँ खरीदी जाती है । इसे वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है ।

(3) <u>आधार मूल्य</u>-
- राष्ट्रीय आय की तुलना के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है ।
- भारत में 2011-12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है ।
- किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य आधार मूल्य कहलाता है ।

(4) <u>स्थिर मूल्य</u>-
- यदि बाजार मूल्य में से मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाये तो वह स्थिर मूल्य कहलाता है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित है- GDP, GNP, NDP, NNP

<u>मौद्रिक राष्ट्रीय आय (Nominal National Income)</u>

इसे प्रचलित या चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (National Income at current price) भी कहा जाता है। इसमें आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में उत्पादन को लेकर वस्तुस्थिति का पता नहीं लग पाता अतः इस राष्ट्रीय आय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता।

इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है–

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{nominal GNP}}{\text{real GNP}}$$

यदि GNP Deflator को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करना हो तो इसके मूल्य को 100 से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष हेतु GNP Deflator का मूल्य 1.25 हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा एवं इसका मान 125 आ जाएगा। इसका अभिप्राय यह होगा कि चालू मूल्य पर जीएनपी वास्तविक जीएनपी के मूल्य का 125% होगा।

Growth v/s Development

संवृद्धि एवं विकास:–

Growth (संवृद्धि) मात्रात्मक होती है तथा राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। विकास गुणात्मक तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।

जीवन के अच्छे गुणवत्ता में आय अथवा ग्रोथ की महत्वपूर्ण भूमिका होती लेकिन आय अथवा ग्रोथ द्वारा जीवन की गुणवत्ता को पूर्ण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ अन्य बातों की आवश्यकता होती है जैसे कि ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि ।

Quality of life:-

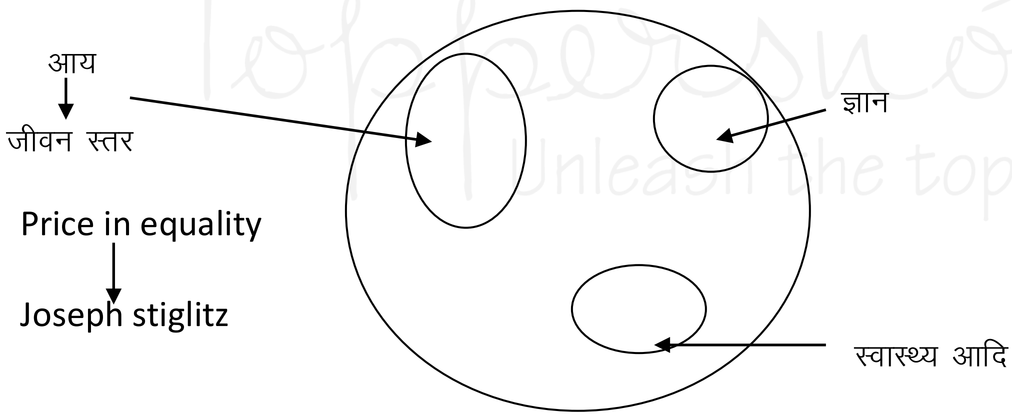

ग्रोथ तथा विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं है यह एक दूसरे के पूरक होते हैं उदाहरण के लिए यदि एक राष्ट्र में अच्छी ग्रोथ है तो उसमें Tax collection का स्तर ऊंचा होगा जिसके द्वारा संबंधित सरकार Education, Health पर Public expenditure बढा सकती है।

इसी प्रकार UNDP के एक रिसर्च के अनुसार यदि साक्षरता की दर को 20% से बढा दिया जाता है तो संबंधित राष्ट्र की ग्रोथ रेट में 5% तक की बढोतरी हो सकती है।

<u>HDI (Human Development Index):-</u>

विकास गुणात्मक होता है इसलिए उसे गणितीय रूप से नहीं मापा जा सकता है लेकिन मोटे रूप में इसकी स्थिति एवं दिशा को समझने के लिए यूएनडीपी द्वारा एचडीआई का निर्माण किया जाता है।

एचडीआई के निर्माण में पाकिस्तान के स्वर्गीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि उनके लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की वास्तविक गरीबी की संकल्पना प्रेरणा का स्रोत रही है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार क्षमताओं का अभाव गरीबी है। उनके अनुसार विकास स्वतंत्रता प्रदायक होता है और एक क्षमतावान व्यक्ति ही स्वतंत्र हो सकता है।

एचडीआई के निर्माण में निम्न आयामों तथा सूचकों का प्रयोग किया जाता है।

Dimension	Indicators
1. आयाम	सूचक
दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन	जीवन प्रत्याशा 168 वर्ष (Life expeciancy)
2. ज्ञान →	स्कूल के औसत वर्ष, (5.4 वर्ष) (Mean years of schooling)
↘	स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, (11.7 वर्ष)
3. जीवन स्तर:-	Real per capita GNI USD: United State Dollors: PPP Based: $5497

Notes:-

1. <u>GNI (Gross National Income)-</u>
   को निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग-

GNP_{mp} = Indirect taxes + Subsidy

↙

GNP_{fc}= GNI

2. यह ध्यान देने योग्य है कि 2010 से पहले UNDP द्वारा GDP_{fc} का प्रयोग किया जाता था लेकिन 2010 में यूएनडीपी द्वारा यह कहा गया कि भूमंडलीकरण के कारण कई राष्ट्रों का जीवन स्तर विदेशी साधन आय से प्रभावित हो रहा है। इसलिए विदेशी साधन आय का ध्यान रखना जरूरी है अतः उसके द्वारा 2010 में जी एन आई के प्रयोग को शुरू कर दिया गया।

Toppersnotes Unleash the topper in you

3. विनिमय दर (exchange rate) दो प्रकार की होती है
   -चालू विनिमय दर।
   -क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर ।

चालू विनिमय दरें मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर को ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए अमेरिकन डॉलर की मांग केवल उसकी क्रय शक्ति को लेकर नहीं होती है। उसकी मांग निवेश एवं अन्य कारणों से भी होती है जिसके चलते उसकी विनिमय दर काफी ऊंची जा सकती है ऐसी अवस्था में क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि यूएनडीपी द्वारा शामिल किए जाने वाले सभी राष्ट्रों की GNI (नई) को अमेरिकन डॉलर्स में बदला जाता है।

4. एचडीआई का मूल्य 0-1 के बीच में होता है और जैसे-जैसे एक की दिशा में एचडीआई का मूल्य बदलता है तो यह माना जाता है कि मानव विकास बढ रहा है। एचडीआई 2015 के अनुसार 2014 के लिए भारत की एचडीआई का मूल्य 0.609 पाया गया।
   भारत का एचडीआई मध्यम मानव विकास को प्रदर्शित करता है।

IHDI(Inequality Adjusted HDI

विषमता समायोजित **,HDI -**
इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया यह माना गया कि विषमताएं quality of life पर विपरीत प्रभाव डालती है । ऐसी अवस्था में एच डी आई में उनका समायोजन जरूरी है।

HDI निकालने के लिए एच डी आई में शामिल किए गए प्रत्येक मानव को लेकर संबंधित राष्ट्र में विषमताओं का पता लगाया जाता है एवं उनके आधार पर एचडीआई के मूल्य को नीचे लाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि भारत को ध्यान में रखा जाए एवं विषमताओं को समायोजित किया जाए तो एचडीआई का मूल्य 0.435 आएगा (2014के लिए) इस प्रकार विषमताओं के कारण भारत का एचडीआई मूल्य 28.6%नीचे चला जाता है।

GDI (Gender Development Index):-
यह महिलाओं के मानव विकास को पुरुषों के मानव विकास के साथ सापेक्षिक रूप से प्रस्तुत करता है इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाताहै-

$$\frac{\text{HDI for females}(0.525)}{\text{HDI for males }(0.660)} = 0.795$$

HPI (Happy Planet Index):-
HDI की एक मुख्य कमजोरी यह है कि इसमें उच्च जीवन स्तर के कारण Environmental Sustainability पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता इस कमी को HPI द्वारा दूर किया गया है। HPI का निर्माण New economic foundation (UK) द्वारा किया जाता है। इसे निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है-